



The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017

Act 13 of 2018

Keyword(s):

Factories, Employment, Workers, Trade Unions

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 29 जनवरी, 2018

माघ 9, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 202/79-वि-1-18-1(क)-08-2017

लखनऊ, 29 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 10 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

संक्षिप्त नाम और
विस्तार

- अधिनियम संख्या 2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित कारखाना अधिनियम, 1948
63 सन् 1948 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ड) में,—
की धारा 2 का संशोधन (एक) उप-खण्ड (एक) में, शब्द "दस या अधिक" के स्थान पर शब्द "बीस या अधिक" रख दिये जायेंगे।
(दो) उप-खण्ड (दो) में, शब्द "बीस या अधिक" के स्थान पर शब्द "चालीस या अधिक" रख दिये जायेंगे।
- धारा 64 का संशोधन 3—मूल अधिनियम की धारा 64 में उपधारा (4) में, खण्ड (चार) में, शब्द "पचास" के स्थान पर शब्द "एक सौ" रख दिये जायेंगे।
- धारा 65 का संशोधन 4—मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (3) में, खण्ड (चार) में, शब्द "पचहत्तर" के स्थान पर शब्द "एक सौ पन्द्रह" रख दिये जायेंगे।
- धारा 66 का संशोधन 5—मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात:—

"परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के संबंध में, इस खण्ड में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है और ऐसे फेरफार से सायं 7 बजे और अगले दिन प्रातः 6 बजे के बीच के घंटों में किसी स्त्री को नियोजन के लिये यह उल्लिखित करते हुये प्राधिकृत किया जा सकता है कि स्त्री की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए आवश्यक उपबंध किये जायें।"

उद्देश्य और कारण

कारखानों में नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, कार्य के घण्टे, अतिकाल, अवकाश तथा अन्य पहलुओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया गया है।

वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा परिणामी प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण के कारण अतिकाल से संबधित उपबंधों को शिथिल करने, रात्रि में महिलाओं को नियोजित करने तथा लघु औद्योगिक ईकाइयों को अधिनियम के आच्छादन से मुक्त करने की माँग बढ़ती रही है। अतः नियोक्ता संघों तथा व्यापार संघों से सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि अतिकाल के घण्टे बढ़ाये जाने तथा कतिपय शर्तों के अधीन रात्रि में महिला कर्मकारों के नियोजन की अनुज्ञा देने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय।

तदनुसार कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 202(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-08-2017

Dated Lucknow, January 29, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Karkhana (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 10, 2018.

THE FACTORIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U. P. ACT NO. 13 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|--|--|
| 1. (1) This Act may be called the Factories (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017. | Short title and extent |
| (2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh. | |
| 2. In section 2 of the Factories Act, 1948 as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (m),— | Amendment of section 2 of Act no. 63 of 1948 |
| (i) in sub-clause (i), for the words “ten or more”, the words “twenty or more” shall be <i>substituted</i> ; | |
| (ii) in sub-clause (ii), for the words “twenty or more”, the words “forty or more” shall be <i>substituted</i> . | |
| 3. In section 64 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (iv) for the word “fifty”, the words “one hundred” shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 64 |
| 4. In section 65 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (iv) for the words “seventy-five” the words “one hundred fifteen” shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 65 |
| 5. In section 66 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b) for the existing proviso, the following proviso shall be <i>substituted</i> , namely:- | Amendment of section 66 |
| “Provided that the State Government may, by notification in the Official <i>Gazette</i> , in respect of any factory or group or class or description of factories vary the limits laid down in this clause and such variation may authorize the employment of any woman between the hours of 7 p.m. and 6 a.m. mentioning therein the provisions for the safety and facilities of the woman to be given to her.” | |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Factories Act, 1948 has been enacted by the Central Government with the object of providing the safety, health, welfare, working hours, overtime, leaves and other aspects of workers employed in factories.

Due to globalization, liberalization and consequent competitive business atmosphere there has been growing demand for relaxing the provisions relating to overtime, employment of women during night and exempting small industrial units from applicability of the Act. So, after due consultation with associations of employers and trade unions, it has been decided to amend the Factories Act, 1948 in its application to Uttar Pradesh to enhance hours of overtime and to permit the employment of women workers during night under certain conditions.

The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 842 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(2615)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 170 सा० विधायी-30-1-2018-(2616)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।